vkj- ,u- vkbZ- ua- UPHIN/2010/32566 Mkd- iath;u- la[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 14 vad % 46 y[kuÅ] xq:okj 14 ekpZ 2024 ls 20 ekpZ 2024 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

२२,२१७ बांड खरीदे गए, २२,०३० हुए कैश, एसबीआई ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया है। इसने अदालत को यह भी बताया कि १ अप्रैल, २०१९ से १५ फरवरी, २०२४ की अवधि के दौरान कुल २२,२१७ बांड खरीदे गए, जिनमें से २२,०३० चुनावी बांड भुनाए गए। हलफनामा बैंक के मुख्य प्रबंध निदेशक दिनेश खारा द्वारा दायर किया गया था। एसबीआई ने कहा कि चुनावी बांड की राशि को चुनावी दलों द्वारा १५ दिनों की वैधता अवधि के भीतर भुनाया नहीं गया था, बल्कि इसे प्रधान मंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया था। हलफनामे में एसबीआई ने कहा कि उसके पास तैयार रिकॉर्ड हैं जिसमें खरीद की तारीख, मूल्यवर्ग और खरीदार का नाम दर्ज किया गया था और राजनीतिक दलों के संबंध में नकदीकरण की तारीख और भुनाए गए बांड के मूल्यवर्ग

दर्ज किए गए थे। उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में १२ मार्च, २०२४ को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति से पहले, इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) में हाथ से वितरित करके भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को उपलब्ध कराया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी कहा कि प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य प्रस्तुत किया गया है। चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, राजनीतिक दलों का नाम जिन्होंने अंशदान प्राप्त कर लिया है, और उक्त बांड का मूल्यवर्ग भी प्रस्तुत कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, एसबीआई ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनावी ब न्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. एसबीआई ने २०१८ में योजना की शुरुआत के बाद से ३० किश्तों में १६,५१८ करोड़ रुपये के चुनावी बांड जारी किए हैं।

नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो या नहीं, सुप्रीम कोर्ट १५ मार्च को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से रोकने के लिए गैर–लाभकारी एसोसिएशन अ फ डेमोक्रेटिक रिफ र्म्स (एडीआर) की याचिका पर १५ मार्च को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। फरवरी में अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद तीन सदस्यीय चुनाव पैनल में दो रिक्तियों के बाद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक, पांडे के इस्तीफे के बाद खाली हुए पद के लिए चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की इस सप्ताह बैठक होने की संभावना है। नए कानून के तहत चयन पैनल में प्रधान मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता इसके सदस्य हैं। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका के जवाब में निर्देश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्तों और अन्य ईसी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष या सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता की समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, २०२३ में सीजेआई के स्थान पर एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया गया, इस कदम को आलोचक देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की देखरेख करने वाले

निगरानीकर्ता को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयास के रूप में देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद से कुछ दिन पहले, अरुण गोयल ने पिछले शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया, यह मोदी सरकार के तहत किसी चुनाव आयुक्त द्वारा दिया गया दूसरा इस्तीफा है। अशोक लवासा ने अगस्त २०२० में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग द्वारा लिए गए विभिन्न आदर्श आचार संहिता उल्लंघन निर्णयों पर असहमति जताई थी।

प्रदेश के २.१२ करोड़ परिवारों को मिलने लगा शुद्ध पेयजल: सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि राज्य में आज दो करोड़ १२ लाख से अधिक परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ है। योगी ने एक उच्चस्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 'हर घर नल–हर घर जल' के संकल्प के साथ प्रदेश के २.६५ करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ से पूर्व मात्र ५.१६ लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। लगातार प्रयासों से आज दो करोड़ १२ लाख से अधिक परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ है। शेष घरों को भी पाइप्ड पेयजल की सुविधा मिले, ऐसे में इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हर घर नल से जल पहुंचाने की यह योजना ईज अ फ लिविंग के संकल्प को पूरा होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह बड़े बदलाव का परिचायक है। यह मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। योगी ने कहा कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में शुद्ध पेयजल एक सपना था। आज यह सपना साकार हो रहा है। यह दोनों ही क्षेत्र शीर्ष प्राथमिकता में है। अतिशीघ्र विंध्य–बुंदेलखंड के हर घर में नल से जल की सुविधा होगी। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मीरजापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य–बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन का कार्य आखिरी चरण

में प्रवेश कर गया है। अवशेष कार्यो को तेजी के साथ पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल केवल प्यास ही नहीं बुझाता, बल्कि अनेक बीमारियों से सुरक्षित भी रखता है। हमें जल के महत्व को समझना होगा। गांव–गांव में लोगों को समझाना होगा। जल संचय के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। जल समितियों को एक्टिव रखें। पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग लें। नुक्कड़ नाटकोंध्लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाएं। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए आम जन को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन से १०० फीसदी संतृप्त गांवों का–हर एक घर का पारदर्शिता के साथ सत्यापन होना चाहिए। अगर एक भी उपभोक्ता असंतुष्ट है तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा किया जाए। हमें स्थलीय निरीक्षण की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा। हर गांव में प्रशिक्षित प्लम्बर की तैनाती कर दी जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में पेयजल के वैकल्पिक प्रबंध कर लिए जाएं। वर्षा कम होने के कारण जलाशयों में अपेक्षोंत कम पानी है। हमें समय रहते इसके लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गर्मी में एक भी दिन एक भी परिवार को पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। योगी ने कहा कि पेयजल परियोजना के कारण जगह–जगह रोड की खुदाई हुई है। इससे आवागमन प्रभावित हो रहा है, दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। कार्यदायी संस्था की यह जिम्मेदारी है कि कार्य समाप्ति के साथ ही सड़क की मरम्मत हो जाए। पेयजल परियोजना के कारण सड़क खराब न रहे। यदि ऐसा हुआ तो जवाबदेही तय की जाए।

आने वाले त्योहारों के बीच योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा

लखनऊ। यूपी में राज्य कर्मचारियों को योगी ससकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों के डीएम में चार प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है। राज्य कर्मचारियों को यह फायदा जनवरी २०२४ से मिलने लगेगा। इसकी अधिसूचना योगी सरकार ने जारी कर दी है। इसी के साथ इस डीएम का फायदा यूपी के १२ लाख पेंशनरों को भी मिलेगा। इस डीएम के बढ़ने से करीब आठ लाख शिक्षकों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकारी खजाने पर कितना पड़ेगा बोझ सरकार के इस बड़े फैसले से उत्तर प्रदेश के प्रदेश के लगभग १० लाख राज्य कर्मचारियों और ८ लाख शिक्षकों को फायदा होगा। होली से ऐन पहले योगी सरकार के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ४ फीसदी बढ़ाने के इस फैसले से सरकारी खजाने पर ३५० करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव

वित्त दीपक कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर उनके पीएफ खाते जमा होगा, जबकि मार्च का डीए अप्रैल में सैलरी के साथ दिया जाएगा।

सम्पादकीय

परदा डालने की भारतीय स्टेट बैंक की कोशिश नाकाम

सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स संबंधित विवरण पर परदा डालने की भारतीय स्टेट बैंक की कोशिश नाकाम कर दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब १५ मार्च को स्टेट बैंक से मिली जानकारियां निर्वाचन आयोग को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होंगी। इससे देश को पता चलेगा कि इन बॉन्ड्स के माध्यम से किन लोगों या उद्योग घरानों ने राजनीतिक चंदा दिया। किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, यह ब्योरा भी आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा। मगर यह सूचना तो पहले से सार्वजनिक दायरे में उपलब्ध है। आशंका जताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही ऐसी बात शामिल है, जिससे कई महत्त्वपूर्ण सूचनाएं जाहिर होने से रह जाएंगी। फिलहाल, यह नहीं मालूम होगा कि किस व्यक्ति या उद्योग घराने ने किस पार्टी को कब और कितना चंदा दिया। अगर ये जानकारियां सामने आतीं, तो सिविल सोसायटी के लोग यह आकलन करने की स्थिति में होते कि केंद्र और विभिन्न राज्यों में सत्ताधारी दलों को किन घरानों से कितना पैसा मिला। फिर वे यह पड़ताल करते कि क्या संबंधित सरकार ने से फैसला लेते वक्त उन खास घरानों के साथ पक्षपात किया। यानी क्या उन घरानों को कोई अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इससे वह पारदर्शिता आती, जिससे भविष्य में धनी–मानी तबकों और राजनीतिक दलों के बीच होने वाली प्रत्यक्ष लेन–देन पर रोक लगती। मगर, स्टेट बैंक ने कह दिया कि यह मिलान करने में उसे बहुत वक्त लगेगा। इस बीच उसके पास चंदा दाताओं और चंदा प्राप्तकर्ताओं की सूची है, जिसे वह सौंप सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि उसने कभी वह ब्योरा देने को नहीं कहा था, जिसके लिए स्टेट बैंक समय मांग रहा है। कोर्ट के इस नजरिए से उन बहुत से लोगों को निराशा हुई है, जो चुनावी चंदे में पूरी जवाबदेही के लिए प्रयासरत रहे हैं। इस तरह उनके नजरिए से देखा जाए, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पारदर्शिता की आंशिक जीत ही है। अब देश के मतदाताओं को अगले आम चुनाव में अपना निर्णय बिना उपरोक्त महत्त्वपूर्ण जानकारी के ही तय करना होगा।

योगी सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों को आवंटित किए गए विभाग

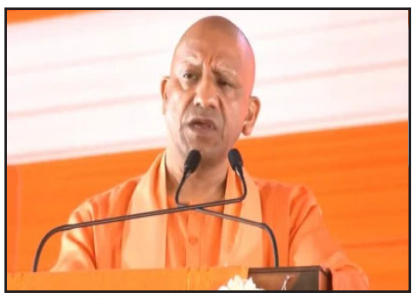

लखनऊ। योगी सरकार में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का मंगलवार को बंटवारा कर दिया गया। नए मंत्रियों में ओमप्रकाश राजभर को पंचायती राज, अल्पसंख्यक कल्याण, हज व मुस्लिम वक्फ विभाग का जिम्मा सौंपा गया। वहीं दारा सिंह चौहान कारागार विभाग संभालेंगे। पहली बार मंत्री बने सुनील शर्मा को सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्र निक्स विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अनिल कुमार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। वहीं योगी मंत्रिमंडल के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मवीर प्रजापति अब नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री बनाये गए हैं। बता दें कि पांच मार्च को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें ओमप्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा व अनिल कुमार को मंत्री बनाया गया है।

सचिवालय संवर्ग के १३ अफसर तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त

लखनऊ। शासन ने स्थानांतरण के बाद कार्यभार ग्रहण न करने पर सचिवालय संवर्ग के १३ अफसरों को तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया। दो अफसरों की वर्तमान तैनाती स्थल पर हाजिरी पर रोक लगाई गई है। इस सिलसिले में मंगलवार को सचिवालय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। बीती १२ जनवरी को विशेष सचिव नियुक्ति विजय कुमार संखवार को कृषि विभाग में विशेष सचिव पद पर तैनात किया गया था, पर उन्होंने अभी तक नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। शासन ने नियुक्ति विभाग से उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त करते हुए कृषि विभाग में कार्यभार ग्रहण करने निर्देश दिया है। इसी तरह १ मार्च को ही विशेष सचिव श्रम जयप्रकाश का स्थानांतरण कर उन्हें विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया, कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें भी तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त कर दिया गया है। बीते एक मार्च को ही विशेष सचिव ग्राम्य विकास सत्य प्रकाश उपाध्याय को विशेष सचिन श्रम के पद पर तबादला होने व कार्यभार ग्रहण न करने पर तत्काल प्रभाव से कार्य मुक्त किया गया है। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में उपसचिव पद पर कार्यरत अजय कुमार तिवारी को उप सचिव वित्त विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण न करने पर कार्य मुक्त किया गया है। उप सचिव नियुक्ति विभाग निरमेश कुमार शुक्ल को उपसचिव औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग के पद पर भेजे जाने व कार्यभार ग्रहण न करने पर कार्यमुक्त किया गया है। उपसचिव पंचायती राज अमिताभ श्रीवास्तव को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग में कार्यभार ग्रहण न करने पर कार्यमुक्त किया गया। इसी तरह विशेष सचिव गृह विश्वजीत सिंह को खेल विभाग में उपसचिव पद के लिए कार्यमुक्त किया गया। लोक निर्माण विभाग के उपसचिव राजकुमार को उपसचिव नियुक्ति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्य मुक्त किया गया। अनु सचिव नियुक्ति विभाग जूली दुबे को लोक निर्माण विभाग में नवीन तैनाती स्थल के लिए कार्य मुक्त किया गया। अनु सचिव नियुक्ति अभिजीत को खाद एवं रसद विभाग के लिए, अनु सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को वित्त विभाग के लिए कार्य मुक्त किया गया। उप सचिव चिकित्सा शिक्षा सत्य प्रकाश सिंह के वित्त विभाग में कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें वर्तमान तैनाती स्थल हस्ताक्षर करने पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह संयुक्त सचिव माध्यमिक शिक्षा ेपा शंकर यादव के भी न्याय विभाग में कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें हस्ताक्षर पर रोक लगा दी गई है।

अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे चुनाव

लखनऊ। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी में कांग्रेस ने अभी तक लोकसभा प्रत्याशी को लेकर कोई इशारा नहीं किया है। हालाँकि कार्यकर्ताओं ने कई बार प्रयागराज, रायबरेली और अमेठी में पोस्टर लगाकर राहुल और प्रियंका को यहाँ से मैदान में उतारने की गुजारिश की। इतना ही नहीं खुद सोनिया गांधी ने जनता के नाम पत्र लिखकर अपनी परंपरागत सीट को लेकर भावुक अपील भी की थी। सूत्रों की मानें तो केरल के वायनाड के अलावा राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी से जुड़े सूत्रों की मानें तो इसको लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तीन राउंड का एक इंटरनल सर्वे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में करवाया गया है। इस सर्वे को कई रिटायर्ड प्रोफेसर और विद्वानों ने किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर राहुल गांध ी का नाम बतौर लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस आलाकमान को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर कांग्रेस कमेटी की तरफ से घोषणा की जा सकती है। वहीं अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री ने कई बार मीडिया के सामने कहा कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। केंद्रीय

मंत्री लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार करने में जुटी हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी उनके कार्यकर्ता जनता को दिलवाने का काम कर रहे हैं।

सीएए लागू होते ही सड़क पर उतरी पुलिस सुरक्षा बल के साथ निकाला फ्लैग मार्च

लखनऊ। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी की गई है। मंगलवार शाम पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर ने सुरक्षा बल के साथ शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने रात के वक्त पेट्रोलिंग और पैदल गश्त बढ़ाने के साथ ही साथ अतिसंवेदन शील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश जारी किया है। पुलिस आयुक्त एसबी शिरडकर मंगलवार शाम शहर का माहौल जानने के लिए सुरक्षा बल के साथ पुराने लखनऊ में फ्लैग मार्च करते दिखाई पड़े। इस दौरान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था उपेंद्र अग्रवाल ने चौक, हुसैनाबाद, नक्खास, नादान महल रोड, वजीरगंज में गश्त के दौरान लोगों को गुमराह न होने की सलाह दी है। इसके साथ ही अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए पुलिसकर्मियों को भी सक्रिय किया। कहाकि, सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड कर माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। वहीं पुलिस आयुक्त ने रात में पेट्रोलिंग और पैदल गश्त बढाने के साथ अतिसंवेदन शील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई जाने का आदेश दिया है।

महिला सिपाही से छेड़छाड़ के आरोपी इंस्पेक्टर का हुआ तबादला

लखनऊ। महिला सिपाही से छेड़छाड़ के आरोपी कृष्णा नगर थाने के इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है। इंस्पेक्टर पर महिला सिपाही ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कृष्णा नगर कोतवाली के कार्यवाहक थाना प्रभारी पर यह आरोप लगा था। एडिशनल इंस्पेक्टर को पद से हटाकर पश्चिमी जोन अटैच किया गया है। संजय कुमार सिंह को कृष्णा नगर का मिला नया चार्ज। इंस्पेक्टर पर लगे आरोपों की जांच विशाखा कमेटी को सौंपी गई है।

अधिवक्ता की पत्नी ने ११वीं मंजिल से लगाई छलांग

लखनऊ। गोमतीनगर सेक्टर–चार के सतलज अपार्टमेंट की ११वीं मंजिल से छलांग लगाकर मंगलवार सुबह अधिवक्ता की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। गोमतीनगर विस्तार थाना प्रभारी निरीक्षक सुधीर अवस्थी ने बताया कि सेक्टर –४ के सतलज अपार्टमेंट के ब्लॉक में अधिवक्ता रामानंद कटिहार पत्नी निशा पटेल (४०) के साथ रहते थे। मंगलवार सुबह अधिवक्ता घर पर नहीं थे, दोनों बच्चे भी स्कूल गए थे। इसी बीच निशा ने ११वीं मंजिल से छंलाग लगा दी। गिरने की आवाज

सुनकर लोगों ने खिड़कियों से झांका, नीचे निशा लहूलुहान हालत में पड़ी थी। शोर–शराब के बीच रामानंद पत्नी को लेकर डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंचे एडीसीपी पूर्वी अमित कुमावत, एसीपी गोमतीनगर अंशु जैन ने परिजन से पूछताछ की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह बात सामने आई कि निशा कई दिनों से बीमार चल रहीं थी। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगा था। जिस वजह से उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आदित्य मिश्रा के सुसाइट पर पत्नी ने उठाए सवाल

लखनऊ। प्रॉपर्टी डीलर आदित्य मिश्रा की सुसाइट को लेकर पत्नी ने सवाल खड़े किए हैं। पत्नी अन्नपूर्णा मिश्रा ने पुलिस को पत्र देकर आत्महत्या की जांच कराने की मांग की है। पत्नी ने पुलिस को दिए गए पत्र में लिखा है कि उसका पति आत्महत्या नहीं कर सकता है। पिछले कुछ समय से लोग उनपर दबाव बना रहे थे। ऐसे में पुलिस मामले की जांच करें। दो दिन पहले आदित्या मिश्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मौके से पुलिस को एक पिस्टल व सुसाइट नोट मिला था। पुलिस का कहना है कि पत्नी द्वार दिए गए पत्र के बाद जांच की जा रही है। घटना के दौरान सुसाइट नोट मिला है पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदित्य मिश्रा की मौत के बाद पुलिस को जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है वह कई सवाल खड़े करता है। ६ प्र पर्टी डीलर व हिंदू युवा सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा की मौत के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है वह चौंकाने वाला है। आदित्य मिश्रा ने अपने सुसाइड नोट में कहा है कि वह संस्कार नगरम नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तमाम प्रयासों के बावजूद कई विभागों से एनओसी नहीं मिल सकती, जिसके चलते व्यवसाय में तगड़ा नुकसान हुआ है। प्रोजेक्ट पूरा न होने के चलते आदित्य मिश्रा तनाव में थे जिसके चलते उन्होंने खुद को गोली मार ली। खुद को मौत के घाट उतारने से पहले आदित्य मिश्रा ने भावुक सुसाइड नोट लिखा है। अपने सुसाइड नोट में आदित्य मिश्रा ने बच्चों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है। सुसाइड नोट में आदित्य मिश्रा ने लिखा कि विनय भैया प्रणाम मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है आपसे ज्यादा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। संस्कार नगराम प्रोजेक्ट अब पूरा नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रोजेक्ट की जमीन बेचकर मेरे बच्चों को पैसा दे दीजिएगा। इस पैसे से वह पल जाएंगे वरना उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, आपका बड़ा एहसान होगा। सुसाइड नोट में आदित्य मिश्रा ने अखिलेश का जिक्र करते हुए लिखा है कि अखिलेश तुमने मेरा बहुत साथ दिया अब बहुत कष्ट में हूं संस्कार नगराम नहीं बस पाया। आदित्य ने उस पिस्टल के बारे में भी सुसाइड नोट में जानकारी दी है जिससे उससे उसने आत्महत्या की। खुलासा करते हुए आदित्य मिश्रा ने लिखा कि एनकाउंटर में मारे गए माफिया विनोद उपाध्याय की पिस्टल से उसने आत्महत्या की है। विनोद उपाध्याय पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया था जिसे ५ जनवरी २०२४ को एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। ६ वर्ष २०१४ में लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता उपेंद्र सिंह उर्फ मोनू की हत्या में आदित्य मिश्रा पर आरोप लगे थे। इसी के साथ लुलु मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में भी पुलिस ने आदित्य मिश्रा को आरोपी बनाया था।

पूर्व डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने सीआईसी पद की ली शपथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने बुधवार को मुख्य सुचना आयुक्त की शपथ ली। मुख्य सूचना आयुक्त के साथ जिन्होंने शपथ ली उनमें मो. नदीम, वीरेंद्र सिंह, सुधीर कुमार,

पद की शपथ ग्रहण की। उन्हें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही १० राज्य सूचना आयुक्त ने भी अपने पद और गोपनीयता राकेश कुमार, दिलीप अग्निहोत्री, राजेन्द्र कुमार सिंह, पदम द्विवेदी, शकुंतला गौतम, गिरजेश कुमार चौधरी और स्वतंत्र प्रकाश शामिल हैं। सीआईसी

पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वालें गिरोह के एक सदस्या को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली

लखनऊ। एसटीएफ यूपी को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के एक सदस्या को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। पिछले दिनों आयोजित की गई पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद से यूपी एसटीएफ द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस ने पेपर लीक गिरोह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज करने के बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी बीच एसटीएफ को महेन्द्र शर्मा पुत्र रामफल को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी बरामद की है। आरोपी को पिल्लुखेडा रेलवे फाटक के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक की बेसमेंट में बनी दुकान से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ पर पता चला कि कि इस कार्य में महेन्द्र पुत्र रामफल निवासी हरियाणा भी शामिल रहा है। जो वर्तमान में हरियाणा में छिपा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी महेन्द्र शर्मा ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक १५–०२–२०२४ को उसके गांव के विक्रम पहल ने उसे इस काम में शामिल किया। यह

दिल्ली पुलिस में काम करता है। विक्रम मुझे अपने साथ मानेसर गुरूग्राम स्थित रिसोर्ट लेकर गया था। जहां पर उसने बताया कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रश्न–पत्र आने वाला है। पेपर लीक कराने के काम में मेरा सहयोग करो तुमको भी एक दो लाख रूपये दूंगा। गुरूग्राम स्थित रिसोर्ट में करीब ३००–४०० परीक्षार्थी पहले से मौजूद थे तथा १०–१२ बसों से अन्य परीक्षार्थी को लेकर गौरव चौधरी रिसोर्ट में आया था। रिसोर्ट का मालिक भी पहले से ही वहां मौजूद था। करीब १००० परीक्षार्थी रिसोर्ट में आ चुके थे। जिसके बाद विक्रम पहल ने सबके साथ मीटिंग की। दिनांक १६–०२–२०२४ को लगभग ११ बजे विक्रम पहल अपने साथियों के साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा दिनांक १८–०२–२०२४ की द्वितीय पाली का प्रश्न–पत्र व उत्तरकुंजी लेकर आया। उसके साथ मोनू शर्मा एवं कुछ अन्य लोग भी आये थे। विक्रम पहल लगातार अपने साथियों के सम्पर्क में था, जिनसे पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न–पत्र आउट कराने को लेकर बात चल रही थी। अभिषेक शुक्ला व रवि के सम्पर्क में विक्रम पहले से था। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में किसी स्थान पर इन लोगों की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आउट कराने व ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को गुरूग्राम स्थित रिसोर्ट में एकत्र करके उनको पेपर पढ़वाने की बात हुई थी।

संयुक्त निदेशक ग्रेड पर 48 चिकित्सक हुए प्रमोट

लखनऊ। प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में संयुक्त निदेशक ग्रेड के ४८ विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी प्रोन्नत हुए हैं। विशेष सचिव शिव सहाय अवस्थी की ओर से मंगलवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक हजरतगंज स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल के परामर्शदाता डॉ. प्रेम प्रकाश को सिविल में ही वरिष्ठ परामर्शदाता की जिम्मेदारी मिली है। इसी तरह बलरामपुर अस्पताल के परामर्शदाता डॉ. नीरज शेखर को भी वरिष्ठ परामर्शदाता की जिम्मेदारी दी गई है। बरेली के जिला महिला चिकित्सालय ड. ललित कुमार, बस्ती के जिला चिकित्सालय के डॉ. विजय शंकर सिंह सहित प्रदेश के ४८ अस्पतालों के विशेषज्ञ वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर प्रमोट किए गए हैं। २३ चिकित्सकों का तबादला शासन की ओर से मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर के २३ चिकित्सकों का तबादला किया गया है। संयुक्त सचिव अजीज अहमद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सीतापुर, उन्नाव, अमरोहा, रायबरेली, शाहजहांपुर, शामली, सोनभद्र, आगरा, कनपुर, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, बहराइच, बदायूं, बाराबंकी और बस्ती के सीएचसी व चिकित्सालय के चिकित्सकों का तबादला किया गया है। डॉ. प्रवीण को मिली बलरामपुर के मनोरोग चिकित्सक की जिम्मेदारी सचिवालय डिस्पेंसरी के परामर्शदाता व मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को बलरामपुर अस्पताल में मनोरोग चिकित्सक के रिक्त पद पर तैनाती दी गई है। इस संबंध में मंगलवार को विशेष सचिव धीरेंद्र सिंह सचान की ओर से आदेश जारी किया गया है।

मंदिर की जमीन पर कब्जेदारी का आरोप लगाने वालों पर ही पुलिस ने दर्ज कर दी प्राथमिकी

लखनऊ। बाजारखाला थानाक्षेत्र स्थित हैदरगंज में मंदिर की जमीन पर कब्जे का विरोध कर रहे लोगों पर मामला उल्टा पड़ गया है। पुलिस ने उन्हें ही आरोपित बना दिया है। थाने में तैनात दरोगा ने १८ नामजद और २५ अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट, बलवा, सरकारी काम में बाधा समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई है। गौरतलब है कि १० मार्च को पुराना हैदरगंज में हनुमान मंदिर की जमीन पर गैर–समुदाए से बिल्डरों द्वारा कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने हंगामा किया था। इस मामले में थाने में तैनात दरोगा नागेन्द्र सिंह चौहान ने प्रदर्शन में शामिल १८ नामजद और २५ अज्ञात लोगों पर मारपीट, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज है। दरोगा ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन सभी आक्रमक हो गए। इस हंगामे के कारण यातायात बाधित हो गया। जबकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि गैर समुदाए के बिल्डर मंदिर की जमीन पर कब्जा कर रहे है। आरोप है कि स्थानीय पुलिस बिल्डर को संरक्षण दे रही है।

पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान नकल करवाने वाने वाले दो बदमाशों को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। एसटीएफ के एसपी (नोएडा यूनिट) राजकुमार मिश्रा ने बताया कि १७ और १८ फरवरी को उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी तथा इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई एवं राज्य शासन ने परीक्षा को रद्द कर दिया। मिश्रा ने बताया कि परीक्षा में नकल करने के मामले में एसटीएफ ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके अनुसार इसके तहत प्रमोद पाठक नामक व्यक्ति को एसटीएफ ने चार मार्च को गिरफ्तार किया था एवं गैंग के अन्य सदस्य मोनू पंडित, मोहन, गौरव, आशीष, अखिलेश, राहुल फरार थे। एसपी ने बताया कि मोनू पंडित की गिरफ्तारी पर झांसी जनपद की पुलिस द्वारा २५ हजार रुपए का इनाम घोषित था। एसपी ने बताया कि आज एक सूचना के आधार पर एसटीएफ ने मोनू पंडित और गौरव को गिरफ्तार किया। दोनों के ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं।

आज भारतीय उत्पाद छा रहे, दुश्मन देश चीन के उत्पाद हो गए बाहर : सीएम योगी

लखनऊ। चीन के उत्पादों को हमने अपने मार्केट से बहुत दूर कर दिया है। यही हमारे एमएसएमई यूनिट्स की ताकत का परिणाम है। इससे बड़ा राष्ट्रवाद क्या हो सकता है, अगर हमारे घर का उत्पाद मार्केट में छा रहा है तो हमें भी उसे प्रोत्साहित करना होगा, प्रेरित करके प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा। ये कितनी खुशी की बात है कि हमारा उत्पाद मार्केट में छा रहा है और दुश्मन देश का उत्पाद मार्केट से दूर होता जा रहा है। आज दीपावली, विजयदशमी, ईद और क्रिसमस पर यूपी के उत्पाद ही मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। हमारा उत्पाद अच्छा तो होता ही है, साथ ही हमारे उद्यमियों और कारीगरों को भी लगता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकभवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान उनहोंने एमएसएमई क्षेत्र के लिए ३०,८२६ करोड़ का मेगा ऋण वितरण किया। साथ ही उन्नाव में स्वीकृत प्लेज पार्क के विकासकर्ताओं को सीएम योगी ने चेक वितरित किया। वहीं उन्होंने औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों के आवंटन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। सीएम योगी ने इस अवसर पर ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूलकिट वितरित किया। मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराए विभाग अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमएसएमई विभाग को मार्केट की संपूर्ण मैपिंग कराते हुए डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट उपलब्ध कराने पर विशेष जोर देना होगा। इसके साथ ही प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर भी खास ध्यान देना होगा। अगर हमने ये काम कर लिया

तो प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को पूरे देश में छाने में बहुत देर नहीं लगेगी। उन्होने एमएसएमई उद्यमियों से भी अपील की कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ तेजी से जुड़ें, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से जुड़े उद्यमियों की ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष २०२३–२४ के समापन के पहले एमएसएमई विभाग की ओर से लोन वितरण के विभिन्न कार्यक्रम हुए हैं। सीएम ने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष वितरित की गई राशि गत वर्ष की तुलना में दोगुना और बीते सात साल की अपेक्षा १० गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह प्रगति यूपी के आर्थिक उन्नयन को तो प्रदर्शित करता ही है साथ ही युवाओं को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। सीएम योगी ने बताया कि प्लेज पार्क से प्रदेश के १० जनपद जुड़ चुके हैं। उन्नाव में बन रहे प्रदेश के ११वें प्लेज पार्क के लिए आज चेक वितरित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई विभाग पिछले सात साल में प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के उद्यमियों के लिए नई आशा की किरण बनकर उभरा है। अपने अभिनव प्रयोग ओर नवाचार के कारण पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में तेजी से आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नये भारत का नया उत्तर प्रदेश है। इसे लेकर बनी पुरानी धरणा को हमने अपने सामर्थ्य से बदला है। आज हमारा हर सेक्टर सभी को उत्तर दे रहा है। यूपी पहले भी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला राज्य था, मगर कुछ लोगों ने इसे बीमारू बना रखा था। हमने इसे राष्ट्रनिर्माण के अभियान के साथ जोड़कर युवाओं और उद्यमियों के डेवलपमेंट के पथ पर अग्रसर किया है। आज इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। यूपी देश का अकेला राज्य है जहां युवा उद्यमियों को बिना ब्याज के पांच लाख का ऋण देने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ६६ लाख एमएसएमई यूनिट्स में से ४० लाख का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमारा लक्ष्य जल्द से जल्द सभी ६६ लाख को रजिस्टर्ड कराना है। सीएम ने कहा कि हमारे पास मजबूत एमएसएमई बेस है, सुरक्षा का माहौल है और पर्याप्त लैंडबैंक है। ऐसे में यहां बड़े उद्योग के लिए बेहतर माहौल बन चुका है। इसकी झलक हमें यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए यूपी को प्राप्त हुए ४० लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव में दिखता है। यही नहीं हाल ही में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए ध्१० लाख करोड़ के निवेश को हमने धरातल पर उतारा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल बैंकर्स की भी सराहना की। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को करना होगा और मजबूत मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस स्पीड से यूपी चल रहा है उसे थोड़ा और पुशअप कर दें तो आने वाले पांच साल में हमें १ ट्रलियन डॉलर इकोन मी बनने में कोई रोक नहीं सकता। सीएम ने कहा कि हमें मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को और अधि ाक मजबूती प्रदान करना होगा। उन्होंने बताया कि पहले निवेश एनसीआर में होता था। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और हापुड़ में निवेश होता था। अब यह काम उन्नाव, हरदोई, जैसे छोटे जिलों में बड़ी संख्या में निवेश हो रहे हैं। ये दिखाता है कि हमारे पास पहले भी पोटेंशियल था, मगर उसका उपयोग नहीं किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र, आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह, एसीएस अमित मोहन प्रसाद, सचिव प्रांजल यादव, आयुक्त एवं निदेशक राजेश कुमार सहित विभागीय अधिकारीगण, उद्यमी और हस्तशिल्पी कारीगर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के हाथों ऋण प्राप्त करने वाले लखनऊ के हामिद अली अंसारी ने बताया कि उन्हें प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए ऋण मिला है। उन्होंने सीएम योगी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी वजह से मुझे अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं बाराबंकी के मोहम्मद इजहार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुझे कोल्ड स्टोर के लिए लोन बिना किसी परेशानी के मिला है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं। सीएम योगी के हाथों सिलाई मशीन टूलकिट प्राप्त करने वाली आशा कुमारी ने भी मुख्यमंत्री का विशेष आभार जताया। इसके अलावा सुल्तानपुर रोड के मनोज कुमार ने कहा कि बिना किसी को एक भी पैसा खिलाए उन्हें ४७ लाख रुपए का ऋण मिला है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।

रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई, पासपोर्ट के चार अधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज

लखनऊ। सीबीआई ने पेमेंट–गेटवे के माध्यम से रिश्वत लेने के आरोप में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद के चार अधिकारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ मंगलवार को एक केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली है। रीजनल पासपोर्ट अ फिस गाजियाबाद के पासपोर्ट असिस्टेंट रवि किशन, चंद्रकांत, सीनियर पासपोर्ट असिस्टेंट पवन कुमार, जंदैल सिंह और प्राइवेट पर्सन मुजफ्फरनगर निवासी मोहम्मद फरहान गौड को मुकदमे में नामजद किया गया है। आरोप है कि पेंडिंग पासपोर्ट के निस्तारण के नाम पर पासपोर्ट असिस्टेंट रविकिशन ने मोहम्मद फरहान गौड़ के जरिये १४ जून २०२२ से १४ जून २०२३ के बीच ७३ हजार रुपए की रकम घूस के रूप में ली। फरहान ने ये पैसा यूपीआई और अपने परिचित लोगों के व लेट, बैंक खाते से ट्रांसफर किया। इसके अलावा पासपोर्ट सहायक चंद्रकांत ने ८ अगस्त २०२२ से ३ जनवरी २०२३ के बीच ५६७०० रुपए मोहम्मद फरहान से लिए। इसी तरह सीनियर पासपोर्ट असिस्टेंट पवन कुमार ने २८ सितंबर २०२२ से २ जुलाई २०२३ के बीच मोहम्मद फरहान से २२६०० रुपए लिए। सीनियर पासपोर्ट असिस्टेंट जंदैल सिंह ने भी १३ जून २०२३ को एक लंबित पासपोर्ट जारी करने के बदले मोहम्मद फरहान से दो हजार रुपए लिए। ये सभी रकम अ नलाइन ट्रांसफर की गई। शुरुआत में सीबीआई ने इसकी आंतरिक जांच की। प्रारंभिक जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। सीबीआई गाजियाबाद की एंटी करप्शन यूनिट ने इसके बाद इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने साझा की गई जानकारी में बताया कि आरोपी व्यक्तियों के मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद स्थित परिसरों की तलाशी ली जा रही है और जांच चल रही है।

हापुड़ में सिपाही ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की

हापुड। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक सिपाही ने सोमवार को अपने घर में खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हाफिजपुर थाना क्षेत्र के गांव चित्तोली निवासी ज नी बाना (३५) मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में सिपाही के पद पर तैनात था। उन्होंने बताया कि वह घर पर आया हुआ था और आज सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मारकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिषेक वर्मा ने बताया कि सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

हापुड़ में भीड़ हिंसा के छह वर्ष पुराने मामले में १० आरोपियों को आजीवन कारावास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की एक स्थानीय अदालत ने मॉब लिंचिंग (भीड़ हिंसा) के करीब छह वर्ष पुराने एक मामले में सभी १० आरोपियों को दोषी ठहराते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने मंगलवार को बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद भीड़ हिंसा से संबंधित मामले में १० आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ५८–५८ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जून २०१८ में हापुड़ के धौलाना के गांव बझैड़ा निवासी कासिम (४५) की गोहत्या के झूठे आरोप में भीड़ ने हत्या कर दी थी। समयदीन (६२) पर भी जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वह बच गया। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी कर जेल भेज दिया था और विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। चौहान ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को हापुड़ की अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)

श्वेता दीक्षित ने सुनवाई के बाद १० आरोपियों धौलाना के बझैड़ा निवासी राकेश, हरिओम, युधि ाष्ठिर, रिंकू, करनपाल, मनीष, ललित, सोनू, कप्तान और मांगेराम को आजीवन कारावास सजा सुनाई और सभी पर ५८–५८ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

सीएए के तहत कैसे मिलेगी नागरिकता, गैर मुस्लिम शरणार्थियों को क्या करना होगा?

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम २०१६ (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता पाने के इच्छुक आवेदक यह साबित करने के लिए वैध या कालातीत (एक्सपायर्ड) पासपोर्ट, पहचान पत्र, भू–रिकार्ड समेत नौ दस्तावेजों में कोई भी एक कागजात जमा कर सकते हैं कि वह अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक हैं। सोमवार को जारी किये गये सीएए नियमों के अनुसार आवेदक यह साबित करने के लिए वीजा और भारत में आगमन पर आव्रजन मुहर सहित २० दस्तावेजों में कोई एक सौंप सकते हैं कि वे ३१ दिसंबर २०१४ से पहले भारत में दाखिल हुए थे। इन दस्तावेजों में किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या किसी राजस्व अधिकारी द्वारा जारी संबंधित प्रमाणपत्र भी शामिल है। नियमों में यह भी कहा गया है कि आवेदकों को किसी स्थानीय प्रतिष्ठित सामुदायिक संगठन से जारी अर्हता प्रमाण पत्र भी देना होगा जो इस बात की पुष्टि करे कि आवेदक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय में किसी एक का सदस्य है और अब भी उसी समुदाय में है। सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया। उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन बिना दस्तावेज वाले गैर मुसलमानों को त्वरित ढंग से नागरिकता देने के लिए इस कानून के नियम जारी किये जो ३१ दिसंबर, २०१४ से

पहले भारत आ गये थे। सीएए के तहत इन तीन देशों के उत्पीड़ित गैर मुसलमानों––हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आवेदकों को इस बात की घोषणा करनी होगी कि वे अपनी वर्तमान नागरिकता का परित्याग करते हैं तथा वे 'भारत को अपना स्थायी निवास' बनाना चाहते हैं। कोई भी आवेदक अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक है, यह साबित करने के लिए वहां की सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट, भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र या आवास परमिट, सरकारी प्रशासनिक इकाई द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल या कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षणिक प्रमाणपत्र शामिल हैं। स्वीकार्य होने वाले अन्य दस्तावेजों में अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान की सरकार या उन देशों के किसी अन्य सरकारी प्रशासनिक निकाय द्वारा जारी पहचान पत्र, कोई लाइसेंस या प्रमाणपत्र और अन्य कागजात शामिल हैं जो यह दर्शाते हों कि आवेदक के माता–पिता, दादी–दादी या नाना–नानी में कोई अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान के नागरिक हैं या नागरिक रहे थे। अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान की सरकार या वहां के किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी ऐसा दस्तावेज भी मान्य होगा जो यह स्थापित करता हो कि आवेदक अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से है। नियमों के अनुसार ये दस्तावेज उनकी वैधता अवधि बीत जाने के बाद भी मान्य होंगे।

सीएए लागू हुआ तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का क्या होगा?

नई दिल्ली। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाली और भारतीय नागरिक सचिन मीना से शादी करने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के कार्यान्वयन के नियमों को अधिसूचित करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है।उन्होंने सीएए लागू करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की और दावा किया कि सीएए से उन्हें भारतीय नागरिकता पाने में मदद मिलेगी। हालाँकि, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता में तेजी लाने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) से हैदर को सीधे लाभ नहीं मिलेगा, बशर्ते वे गैर–मुस्लिम हों और ३१ दिसंबर २०१४ से पहले भारत आए हों। 'भारत सरकार ने आज हमारे देश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम लागू कर दिया है। हम इससे बहुत खुश हैं और इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं। वास्तव में, मोदी जी ने जो वादा किया था वह किया है। मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूंगी। उन्हें धन्यवाद देते रहो। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने कहा, 'इस खुशी के मौके पर, मैं अपने भाई वकील एपी सिंह को उनके काम के लिए बधाई देती हूं क्योंकि अब इस कानून से मेरी नागरिकता संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। वीडियो में वह 'जय श्री राम', 'राधे राधे' और 'भारत माता की जय' कहती नजर आ रही हैं। उनके वकील सिंह ने भी केंद्र की घोषणा की सराहना की और कहा कि इस फैसले से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के विभिन्न धर्मों के लोगों को मदद मिलेगी जो भारत में नागरिकता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। सिंह ने कहा, 'यह उन लोगों के लिए एक बड़ा दिन है जो इन देशों में प्रताड़ित हुए और किसी तरह यहां (भारत) अपना गुजारा कर सके।ष मूल रूप से पाकिस्तान

के सिंध प्रांत के जकोबाबाद की रहने वाली सीमा को ग्रेटर नोएडा में एक भारतीय नागरिक सचिन मीना, जो अब उसका पति है, के साथ अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा गया था। पिछले मई में, वह नेपाल के रास्ते भारत की यात्रा के लिए अपने बच्चों के साथ कराची स्थित अपना घर छोड़कर चली गई। फरवरी में, हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने अपने चार बच्चों की कस्टडी मांगने के लिए एक भारतीय वकील को नियुक्त किया। संसद द्वारा विवादास्पद कानून पारित करने के चार साल बाद नियमों को अंतिम रूप देते हुए सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम २०१६ लागू किया। इस कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता में तेजी लाना है, जो गैर–मुस्लिम हैं और ३१ दिसंबर २०१४ से पहले भारत आए थे। मोदी सरकार अब प्रताड़ित गैर–मुस्लिम प्रवासियों–हिंदुओं, सिखों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू करेगी।

पीएसी की १७६ व सीएपीएफ की १०० कंपनी तैनात, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ। नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद यूपी पुलिस के सामने शांति व्यवस्था को बनाए रखना चुनौती बना हुआ है ऐसे में डीजीपी यूपी ने आलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी को ओर से अधिकारियों को निर्देशित करते हुए वर्ष २०१६ व २०२० में सीएए को लेकर हुई हिंसा लेकर, डाटा तैयार कर इन क्षेत्र व लोगों पर नजर रखने को कहा है जिससे दोबारा से ऐसी घटनाएं न होने पाएं। दूसरी ओर डीजीपी के निर्देशों के बाद सोशल मीडिया में २४ घंटे नजर रखी जा रही है। डीजीपी के साफ निर्देश है कि इस दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस २४ घंटे सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि सीएए के लागू होने के बाद से अलर्ट जारी किया गया है। यूपी पुलिस हर एंगल पर तैयार है ऐसे में यदि कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। डीजीपी ने कहा है कि पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नागरिकता संशोधन कानून को सरकार जल्द ही लागू की करेगी। जिसको लेकर पहले से ही तैयारी कर रखी है। फील्ड अफसरों को सतर्क किया गया है। फील्ड अफसरों ने कानून लागू होते ही सभी धार्मिक नेताओं, धर्म गुरुओं, पीस कमेटी के सदस्यों सहित सिविल डिफेंस के लोगों से वार्तालाप करने के लिए कहा गया है। डीजीपी ने कहा है कि, यह कानून पड़ोसी देशों से धार्मिक कारण से परेशान होकर भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने का कानून है। इस कानून से किसी की भी नागरिकता छीनेगी नही, और इस लोगों की संख्या बहुत ही कम है। धर्म गुरुओं से बातचीत करने का असर भी देखने को मिल रहा है, कानून को समझने के बाद सभी धर्मगुरुओं और धर्म नेताओं ने सकारात्मक बयान जारी किए है। ऐसे में यह आशा है कि धीरे धीरे सभी लोग इस कानून के विषय में समझ लेंगे। १०० कंपनी सीएपीएफ, १७६ कंपनी पीएसी को तैनात किया गया है। जितने भी टेक्निकल संसाधन है, जैसे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, बाईना कुलर का भी इस्तमाल किया जा रहा है। फील्ड पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर मार्च कर रहे है। उपद्रव करने वाले संवेदनशील लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। सभी पर नजर रखी जा रही है। पुलिस मुख्यालय और जिला स्तर पर मौजूद सोशल मीडिया म निटरिंग सेल पर २४ घंटे नजर रखी जा रही है। डीजीपी ने कहा यदि कोई भी कानून को लेकर अफवाह या व्यामस्ता फैलाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अंकुश राजा का भोजपुरी होली स्पेशल भक्ति गीत 'होली खेले राम लला' रिलीज

मुंबई। अंकुश राजा का होली स्पेशल भक्ति गीत 'होली खेले राम लला' रिलीज हो गया है। 'होली खेले राम लला' गीत के माध्यम से अंकुश राजा ने अवध की होली का बखान किया है और बताया है कि कैसे राम लला भी अवध में होली खेला करते थे। अंकुश राजा का यह होली गीत उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चौनल अंकुश राजा भक्ति पर रिलीज हुआ है। 'होली खेले राम लला' में अंकुश राजा ने भगवान राम की रघुराई और अवध की रंग बिरंगी होली को अपने गीत में प्रयोग कर पेश किया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि होली में अलग–अलग तरह के गीत–संगीत का दौर चलता रहता है, लेकिन हमने इस बार राम लला के आगमन की खुशी में यह गीत बनाया है, और हम उनके चरणों में समर्पित भी करते हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली

होली है ,जिससे हम लोग पूरी आस्था के साथ मनाने वाले हैं और उसमें हमारा यह गीत होली को और भी खास बना देगी। 'होली खेले राम लला' के गीतकार छोटू रावत और संगीतकार रजनी रंगीला हैं। वीडियो आशीष सत्यार्थी का है।

नगर निगम में निर्माण कार्य में जमकर हो रहा भ्रष्टाचार

लखनऊ। नगर निगम के अभियंत्रण विभाग में निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। जिसे अभियंत्रण विभाग का संरक्षण मिल रहा है। न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के अमन विहार की गली नंबर ६ में एक सप्ताह पूर्व पार्षद निधि से सड़क सुधार के लिए १० लाख रुपये से हो रहे कार्य में ठेकेदार ने तीन गाड़ी पुरानी टाइल्स बाहर से लाकर लगा दी। पार्षद रजनी गुप्ता ने महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त इन्द्रजीत सिंह को पत्र लिखकर जेई और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सूचना देने के बाद भी जेई ने काम नहीं रोका। ठेकेदार द्वारा किये जा रहे घटिया निर्माण को मोहल्ले वालों ने रोका। पार्षद का कहना है कि शिकायत पर ही जेई मौका मुआयना करने जाते हैं। नहीं तो बैठे–बैठे बिल बना देते हैं। निर्माण एवं सुधार कार्य जेई की देख–रेख में कराये जाने का कई बार आग्रह करने के बाद भी सुनवाई नहीं की जाती है।

मुख्यमंत्री योगी ने इन्वेस्ट यूपी के नए वीपिबम का किया उद्घाटन

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इन्वेस्ट यूपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया तथा इन्वेस्टर्स के साथ संवाद भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते ७ वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए बहुत से रिफ र्म किए गए हैं और आगे भी रिफ र्म होने जा रहे हैं, क्योंकि यह आज की आवश्यकता है। यूपी को वन ट्रिलियन ड लर की इकोन मी के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना ही पड़ेगा। फैसिलिटेशन की सुविधा अधिक से अधिक उपलब्ध करानी ही पड़ेगी और उस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि देश और दुनिया के इन्वेस्टर्स जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है, उनके विश्वास पर यह नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी तरह खरा उतरकर उनकी भावनाओं के अनुरूप एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उन्हें उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर निवेशकों ने यूपी में निवेश को लेकर अपनी राय रखी और सुझाव भी दिए। सीएम योगी ने सभी को ध्यान से सुना। इससे पहले सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी की बुकलेट का भी विमोचन किया। सीएम योगी ने कहा कि आज से ७ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश पर कोई विश्वास नहीं करता था। हम जिससे भी बात करते थे वह उत्तर प्रदेश से अपने निवेश को ले जाने की बात तो करता था लेकिन लाने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता था। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होता है यूपी उसकी एक नजीर प्रस्तुत करता है। ४० लाख करोड रुपए के निवेश प्रस्तावों के साथ

ही अभी हाल में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से १० लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यह एक कल्पना थी, लेकिन वह आज हकीकत बन चुकी है। यह आप सबके विश्वास के कारण हुआ है। इसके लिए, आप सबका ह्रदय से अभिनंदन करता हूं। आपने नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को देखा है। इसमें आप अपना व्यवसाय भी लगा रहे हैं। सुरक्षा का बेहतर माहौल है तो अत्यधिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है। एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, रेलवे का डेडिकेटेड फ्रेट क रिडोर हो, आज यूपी में बेहतर कनेक्टिविटी है। सीएम योगी ने कहा कि कनेक्टिविटी में आज देश के अंदर सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। प्रधानमंत्री जी ने परसों आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। कल से ही वायु सेवा उन एयरपोर्ट्स पर प्रारंभ हो चुकी है और यह पूरी तरह फुल होकर जा रही है। आजमगढ़ जिसके नाम से पहले लोग डरते थे, आज वायु सेवा से जुड़ चुका है। एयरपोर्ट, हाईवे, यूनिवर्सिटी वहां पर स्थापित हो चुकी है। श्रावस्ती नेपाल से सटा हुआ छोटा सा जनपद है, लेकिन वहां पर एयरपोर्ट, वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। पहले यूपी में इन्वेस्टमेंट एनसीआर में ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद तक सीमित होता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सभी ७५ जनपदों में निवेश हुए हैं। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में निवेश समान रूप से पूरे प्रदेश को ध्यान में रखकर हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश के साथ ही देश की इकोन मी के लिए बहुत मायने रखता है।सीएम ने आगे कहा की यूपी के अंदर टेक्नोल जी का उपयोग करके हमने इन्वेस्टर को विश्वास दिलाया है कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हर एक इन्वेस्टर हमारे लिए अभिनंदनीय होना चाहिए। हमें उसको अधिकाधिक सुविधा संपन्न बनाना होगा और सुरक्षित माहौल भी देना होगा। सुरक्षित माहौल में उनके साथ हमारा व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए। हमारा व्यवहार शासक और प्रजा का नहीं बल्कि हम प्रजा के सेवक के रूप में कार्य करेंगे। वह यहां निवेश करेगा तो उसकी सुरक्षा की गारंटी हमको देनी ही पड़ेगी। हरेक प्रकार की सुरक्षा उसको उपलब्ध कराना शासन की मंशा है। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इसी के लिए हमने यूपी में अपनी प लिसीज तैयार कीं। प लिसी के दायरे में रहकर हर निवेशक को उनके इंसेंटिव को भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बैरियर इस मार्ग में नहीं आएगा। बैरियर आएगा तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमें जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, हम उठाएंगे। यह उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के साथ–साथ डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य की एक टीम ने हाल ही में मुझसे पूछा कि क्या आपके यहां सचमुच यूपी का बजट आज ७.५ लाख करोड़ का है? आज से ६ वर्ष पहले तो यह २ लाख करोड़ का था। तब हमने कहा कि यह ६ वर्ष पहले का यूपी नहीं है। यह नया यूपी है और इस नए यूपी में ७.५ लाख करोड़ से ही हम संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। हमारा मानना है कि यह १० लाख करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि ग्राउंड ब्रेकिंग में जो आपके डाटा आए हैं क्या यह अ र्गेनिक हैं। मैंने कहा यही प्रश्न तब भी उठाते थे जब हमने यहां पर इन्वेस्टर समिट किया था। तब मौन रहा और कहा कि इसका जवाब समय देगा। अब उन्हीं लोगों के फोन आने लगे हैं कि आपके सभी डाटा अ र्गेनिक हैं। हमारा जो भी कार्य है सब टेक्नोल जी पर आधारित है। अ नलाइन है तो आप इसकी म नीटरिंग कर सकते हैं इसको देख सकते हैं। इस अवसर पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी, ंषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, आईआईडीसी मनोज कुमार सिंह और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश उपस्थित रहे।

परिवहन मंत्री ने 41.16 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास

लखनऊ। योगी सरकार ने पहली बार परिवहन निगम को बजट में ५०० करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस धनराशि से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। पीपीपी मॉडल से हवाई अड्डों की तरह बस स्टेशनों का निर्माण कराया जा रहा है। ये बातें मंगलवार को परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहीं। परिवहन राज्यमंत्री ने कहा कि पहले पीपीपी म डल पर लखनऊ का आलमबाग बस स्टेशन बनाया गया था। अब इसी तरह ११ बस स्टेशनों को भी पीपीपी म डल पर बनाने की तैयारी है। मंत्री ने मंगलवार को परिवहन निगम सभागार में परिवहन विभाग एवं परिवहन निगम की ४१.१६ करोड़ रुपये की लागत की कुल १८ परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि ११ परियोजनाओं का शिलान्यास और ४ का लोकार्पण किया गया है। बरेली का फरीदपुर बस स्टेशन नया बनाया गया है। रायबरेली के बछरावां और महाराजगंज बस स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। परिवहन निगम मुख्यालय में नया कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। सेंटर का भी मंगलवार को लोकार्पण हुआ। परिवहन मंत्री ने बताया कि बसों में वीएलटीडी (व्हीकिल लोकेशन एंड ट्रैकिंग डिवाइस) के साथ पैनिक बटन भी लगाया गया है। जिसका उपयोग करने पर निगम मुख्यालय स्थित कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर एवं सम्बंधित क्षेत्रीय कन्ट्रोल रूम में मौजूद अधिकारियों को संकेत मिलेगा। बस में यात्री पैनिक बटन दबाता है तो कंट्रोल कमांड सेंटर से उसे तत्काल मदद भेजी जाएगी। बताया कि जल्द ही एक एप लांच किया जाएगा। इस एप पर रेलवे की तरह यात्री को पता चलेगा कि उनकी बस कहां पहुंची है। कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से बसों की वास्तविक स्थिति प्रदेश के लोगों को पता चलेगी। वास्तविक लोकेशन प्राप्त कर किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सकती है। कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर को डॉयल ११२ से भी जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू, परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह, विशेष सचिव परिवहन केपी सिंह, परिवहन निगम के मासूम अली सरवर और मारुति सुजुकी के वाइस प्रेसीडेंट तरुण अग्रवाल उपस्थित रहे। परिवहन मंत्री ने बताया कि रायबरेली स्थित इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेन्टर का लोकार्पण भी किया गया है। यह देश का पहला ऐसा सेन्टर है, जहां ट्रेनिंग, टेस्टिंग के साथ रिसर्च भी होगा। इस सेन्टर के संचालित होने से प्रदेश को कुशल चालक मिलेंगे। इससे सड़क दुर्घटनाओं में ५० प्रतिशत तक कमी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में डीटीटीआई और प्रतापगढ़ में एडीटीटी का लोकार्पण से ड्राइवरों की ट्रेनिंग अब ऑनलाइन हो सकेगी। मैनुअल ट्रेनिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्व में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश की इकोन मी को एक ट्रिलियन बनाने में परिवहन निगम का बहुत बड़ा योगदान होगा। परिवहन निगम में नई यूरो–६ मॉडल की अत्याधुनिक बसें चलायी जा रही हैं, साथ ही ५ हजार नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से प्रदूषणमुक्त एवं आरामदायक सेवा प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में परिवहन निगम को देश का नंबर वन परिवहन निगम बनाएंगे।

माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा

लखनऊ। दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब तेजी से होने लगा है। एक के बाद एक उसके किये गये जुर्मों की सजा न्यायालय से मिलने लगी है। न्यायालयों में चल रहे मामलों में योगी सरकार द्वारा की जा रही प्रभावी पैरवी के कारण माफिया मुख्तार अंसारी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। तीन दशक पुराने मामले में मुख्तार अंसारी के दोषी पाये जाने के बाद बुधवार को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसपर २ लाख २ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अंसारी को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अबतक आठ मामलों में माफिया को सजा सुनाई जा चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी, अवनीश गौतम की अदालत ने मुख्तार अंसारी को डीएमध्एसपी के फर्जी हस्ताक्षर पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में सजा सुनाई है। १९९० में थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर में दर्ज तीन और कोतवाली गाजीपुर में दर्ज एक मामले में हुई सुनवाई और प्रभावी पैरवी के बाद चारों धाराओं में अलग अलग सजा सुनाई गई है। इसमें ४२०/१२० बी आईपीसी में सात साल, ४९७/१२० बी आईपीसी में आजीवन कारावास, ४९८/१२० बी में ७ वर्ष और ३० आयुध अधिनियम में ६ माह की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी पर अलग–अलग कुल २,०२,००० रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर १ साल १ हफ्ते के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है। मालूम हो कि इससे पहले योगी सरकार की प्रभावी पैरवी

के कारण कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में भी माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सुनाई जा चुकी है। मुख्तार अंसारी को अब तक कुल आठ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इससे पहले दिसंबर २०२३ में वाराणसी की एमपीध्एमएलए कोर्ट ने २६ साल पुराने कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा की हत्या के गवाह महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी पाते हुए साढ़े पांच साल की कठोर कारावास और १० हजार जुर्माने की सजा सुनायी थी।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर, एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग को भेजी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के एक दिन बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का डेटा सौंपा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया और उसे १२ मार्च को व्यावसायिक घंटों के अंत तक चुनाव आयोग को चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पोल पैनल को १५ मार्च को शाम ५ बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने १५ फरवरी को

दिए अपने फैसले में इसे असंवैधानिक करार दिया था। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि १२ अप्रैल २०१६ के बाद से हुई चुनावी बॉन्ड की खरीद से जुड़े डीटेल्स ६ मार्च २०२४ तक इलेक्शन कमिशन को सौंप दे। ऐसे में लगभग इस पूरी अवधि के निकल जाने के बाद एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के पास ३० जून तक का वक्त देने का अनुरोध लेकर आया। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि १५ फरवरी और ११ मार्च, २०२४ के अपने आदेश में शामिल ैठप् को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड पर डेटा प्रदान किया गया है।

किसानों को मिली दिल्ली में महापंचायत की इजाजत

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली एक दिवसीय शकिसान

महापंचायतश की अनुमति दे दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। किसान नेताओं द्वारा रखी गई कुछ शर्तों पर सहमत होने के बाद ही इजाजत दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि समझौते पर दिल्ली पुलिस और एसकेएम के वरिष्ठ सदस्यों पी कृष्ण प्रसाद, हनान मोल्ला, प्रेम सिंह गहलावत और आशीष मित्तल के बीच हस्ताक्षर किए गए। पहले किसान नेताओं ने दावा किया था कि कई राज्यों से किसान राष्ट्रीय राजधानी में जुटेंगे, जिनमें अकेले पंजाब से ५०,००० से अधिक किसान शामिल होंगे। हालाँकि, समझौते के तहत, आयोजन स्थल पर ५,००० से अधिक प्रतिभागियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। बताया जाता है कि इस मैदान की क्षमता करीब १.२५ लाख है। साथ ही, कोई भी भड़काऊ या डराने वाला भाषण नहीं दिया जाएगा और महापंचायत के बाद कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। यदि कोई भड़काऊ भाषण दिया जाता है, तो सार्वजनिक संबोधन प्रणाली बंद कर दी जाएगी और वक्ताओं को मंच से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, रैली उस दिन दोपहर ३ बजे तक समाप्त होनी चाहिए और इससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम से पहले और बाद में शहर में रात नहीं बिता सकता है। इस बीच, महापंचायत की पूर्व संध्या पर, दिल्ली यातायात पुलिस ने एक यातायात परामर्श जारी किया, जिसमें यात्रियों को यातायात नियमों और मार्गों में बदलाव के बारे में सचेत किया गया। एडवाइजरी में कहा गया है कि चुनिंदा मार्गों पर सुबह ६ बजे से शाम ४ बजे तक यातायात की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। सुबह ६ बजे से कुछ अन्य सड़कों पर डायवर्जन लगाया जा सकता है। इसलिए, लोगों को तदनुसार अपने आवागमन की योजना बनानी चाहिए।

६ महीने की ट्रेनिंग वाले अग्निवीरों का सामना चीनी सैनिकों से हो जाए तो क्या होगा? चली जाएगी जान, महाराष्ट्र में राहुल ने दिया बयान

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के धुले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस श्नारी न्यायश के अपने लक्ष्य को घर–घर तक लेकर जाएगी और देश की आधी आबादी को उनका पूरा हक दिलाएगी। महाराष्ट्र के दोंडाइचा

में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि चीनी सेना के जवानों को ३–४ साल तक आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है। अगर हमारे अग्निवीरों को, जिन्हें छह महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, चीनी सैनिकों का सामना करना पड़ जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि तब क्या होगा? हमारा अग्निवीर बिना प्रशिक्षण के जाकर अपनी जान दे देगा लेकिन फिर भी उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला न्याय गारंटी योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को १ लाख रुपये, सरकारी नौकरियों में ५० प्रतिशत आरक्षण और महिलाओं को छात्रावास की सुविधा देने का वादा किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को 'नारी न्याय' गारंटी की घोषणा की और कहा कि इससे देश की महिलाओं के लिए समृद्धि का द्वार खुलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक वीडियो जारी कर और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान महाराष्ट्र के धुले में 'नारी न्याय' के तहत पांच कदमों की घोषणा की। पार्टी की ओर से घोषित 'नारी न्याय' गारंटी के तहत किए गए प्रमुख वादों में हर साल गरीब परिवार की महिला को एक लाख रुपये देना और केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं की ५० प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात शामिल है।

पत्नी और बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति और उसकी साली को आजीवन कारावास की सजा

कौशांबी। कौशांबी जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी और बेटी की हत्या करने के चार साल पुराने मामले में एक व्यक्ति और उसकी साली को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) पूर्णिमा प्रांजल ने मंगलवार को अजय साहू और उसकी साली कविता साहू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी और ३५–३५ हजार रुपये जुर्माना लगाया। चौधरी ने बताया कि १४ अक्टूबर २०२० को निवासी राजेश साहू ने सैनी थाने में सूचना दी थी कि उनकी बेटी सरिता (३०) तथा नातिन तनु (आठ) की हत्या दामाद अजय साहू और उनकी दूसरी बेटी कविता साहू (२५) ने प्रेम प्रसंग के चलते कर दी है। पुलिस ने हत्या और साजिश का मामला पंजीत कर विवेचना पूरी कर आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने आज अजय साहू और कविता साहू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

गूगल ने झूठी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग से हाथ मिलाया

नयी दिल्ली। अल्फाबेट इंक के स्वामित्व वाली कंपनी गूगल ने आगामी चुनावों के दौरान झूठी सूचना के प्रसार की रोकथाम, अधिकृत सामग्री को बढ़ावा देने और कृत्रिम मेधा (एआई)

के जरिये उत्पन्न डेटा का उपयोग करने के लिए निर्वाचन आयोग से हाथ मिलाया है। गूगल इंडिया ने एक ब्ल ग पोस्ट में मंगलवार को कहा कि इसके उत्पाद चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधिकारिक सूचना बढ़ाने की विशेषताओं से लैस किये गए हैं। गूगल ने कहा, "हम मतदान के बारे में गूगल सर्च पर अंग्रेजी और हिंदी में महत्वपूर्ण जानकारी ढूंढने में लोगों की सहायता के लिए सहयोग कर रहे हैं। इन जानकारियों में, पंजीकरण कैसे करें और मतदान कैसे करें शामिल हैं।" अधिक संख्या में लोगों केंत्रिम मेधा का इस्तेमाल करने के विषय पर गूगल ने कहा कि यह ऐसी प्रक्रियाएं तैयार कर रही है जो उपयोगकर्ताओं कोंत्रिम मेधा सामग्री की पहचान करने में मदद करेगी। इसने कहा, "अधिक विज्ञापनदाताओं द्वारा एआई की शक्ति और अवसर का लाभ उठाये जाने पर, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम अधिक पारदर्शिता और विषय पर सभी जानकारियों के साथ लोगों को निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते रहें।" गूगल ने कहा, "हमारी विज्ञापन नीतियां पहले से ही, गुमराह करने वाली 'डीपफेक' या छेड़छाड़ की गई सामग्री के उपयोग को निषिद्ध करती हैं।" गूगल ने इस बारे में कड़ी नीतियां एवं पाबंदियां निर्धारित की हैं कि चुनाव संबंधित विज्ञापन उसके मंचों पर कौन जारी कर सकता है। इनमें निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान का सत्यापन, प्रमाणन और अधिंत किया जाना शामिल है।

कार के बस से टकरा जाने के कारण चालक सहित तीन की मौत

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले में प्रयागराज–लखनऊ राजमार्ग पर मंगलवार रात एक कार के अनियंत्रित होकर रोडवेज बस से टकरा जाने के कारण कार चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गयी और दो महिलाएं घायल हो गयीं। पुलिस ने यह जानकारी दी। कुंडा के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अजीत सिंह ने बताया कि कार सवार लोग प्रयागराज से मनगढ़ धाम दर्शन करने जा रहे थे तभी प्रयागराज–लखनऊ राजमार्ग पर बिसहिया गांव के निकट उनका वाहन अनियंत्रित होकर सामने से आ रही रोडवेज बस से टकरा गया। सीओ ने बताया कि हादसे में कार सवार सभी लोग घायल हो गए, जिनको स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने अनुज गोस्वामी (३२), वैष्णवी गोस्वामी (३०) और

गुनगुन गोस्वामी (छह) को मृत घोषित किया। उन्होंने बताया कि अनीता गोस्वामी (४०) और ट्विंकल गोस्वामी (२५) को प्रयागराज रेफर कर दिया स पुलिस शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

विकसित भारत के एंबेसडर ऑफ द वीक बने उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए विकसित भारत अभियान में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को 'एंबेसडर ऑफ द वीक' चुना गया है। उन्हें नमो ऐप के विकसित भारत कार्यक्रम में इस सप्ताह देशभर में आम नागरिकों ने सबसे ज्यादा बार पसंद किया। नमो एप पर उनके लिंक से सबसे ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड किया। प्रधानमंत्री ने एक से पांच स्थान पाने वालों को शुभकामनाएं दी है, इसमें चौथा स्थान लखनऊ के भाजपा कार्यकर्ता अनुराग श्रीवास्तव ने हासिल किया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नमो ऐप पर "विकसित भारत एंबेसडरश्श नाम से एक मॉड्यूल पेश किया गया है। मोदी ने दिसंबर २०२३ में नमो ऐप डाउनलोड करके विकसित भारत एंबेसडर बनने का आह्वान

किया था। मोदी हर हफ्ते इसे लेकर एक रैंकिंग जारी करते हैं। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को सप्ताह का नंबर वन चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी है। श्री पाठक ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मोदी ने दूसरा स्थान पाने वाले चितरंजन कुमार, तीसरा स्थान पाने वाले डा. पंकज सिंह, चौथा स्थान पाने वाले भाजपा कार्यकर्ता अनुराग श्रीवास्तव और पांचवा स्थान पाने वाली सीमा हिरय को भी बधाई दी है। इन सभी को चार मार्च से १० मार्च के सप्ताह के लिए विकसित भारत अंबेसडर चुना गया है। नरेंद्र मोदी डॉट इन नाम के एक्स अकाउंट पर ये लिस्ट जारी की गई है, जिसके साथ एक नोट भी लिखा गया है, जिसमें कहा गया है, "इस सप्ताह शीर्ष पांच विकसित भारत राजदूतों को बधाई! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए आपका समर्पण प्रेरणादायक और सराहनीय है।"

शाहरुख खान को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस रहीं कियारा आडवाणी

मुंबई। २२ वें जी सिने अवार्ड में ब लीवुड के किंग खान शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला। २२ वें जी सिने अवार्ड में शाहरूख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। रानी मुखर्जी और आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स पुरस्कार से नवाजी गई। कियारा आडवाणी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ज्यूरी का पुरस्कार मिला। बेस्ट वीएफएक्स–जवान के लिए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट,बबेस्ट एक्शन–स्पाइरो रजाटोस, एनल अरासु, क्रेग मैक्रे और जवान के लिए टीम,बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक–जवान के लिए अनिरुद्ध, बेस्ट डायलॉग–जवान के लिए सुमित अरोड़ाबेस्ट प्ले बैक सिंगर मेल–अरिजीत सिंह (पठान से झूमे जो पठान), बेस्ट प्ले बैक सिंगर

फीमेल–शिल्पा राव (बेशरम रंग फिल्म पठान) बेस्ट लिरिक्स–कुमार (चलिया–पठान) के लिये चुने गये। वहीं बेस्ट कस्टूमए डिजाइन–मनीष मल्होत्रा (रॉकी और रानी की प्रेम कहानी),परफॉर्मर ऑफ द इयर मेल– कार्तिक आर्यन, बेस्ट कोरियोग्राफी–बॉस्को मार्टिस (झूमे जो पठान) के लिये पुरस्कृत किये गये। आययुष्मान खुराना और अपारशक्ति खुराना ने जी सिने अवॉर्ड शो को होस्ट किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिये फिल्म जवान को पुरस्कार मिला। जी सिने अवॉर्ड्स २०२४ में कई सितारों ने रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। इस लिस्ट में शाहरुख खान से लेकर सनी देओल, बॉबी देओल, कृति सेनन, सोनू निगम समेत कई जानी–मानी हस्तियां शामिल हुई।

हिना खान की सादगी देख फिदा हुए फैंस

मुंबई। टीवी से बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस हिना खान आए दिन सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर अपने जलवे बिखरती रहती हैं। अब फिर से हिना का नया लुक वायरल हो रहा है। हिना ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वह अपनी दिलकश अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। हिना खान इन तस्वीरों में फ्लोरल डिजाइन येलो कलर का सूट पहना है, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग लॉन्ग शर्ग पहना है। इस लुक में वो कयामत ढा रही हैं।

हिना येलो सूट, पलाजो ट्राउजर और मल्टी कलर दुपट्टा पहने बेहद खूबसूरत लग रही हैं। इन तस्वीरों में हिना खान पार्क में शानदार ढंग से टहलती हुई दिखाई दें रही हैं। हिना के चाहने वाले उनके इस अंदाज पर से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं। हिना खान के लुक की बात करें तो येलो सूट के साथ एक्ट्रेस ने झुमके, स्टाइलिश जूतियां पहनी हैं। हिना खान का मेकअप भी काफी जच रहा है। इन फोटोज में एक्ट्रेस एक दम कमाल की लग रही हैं। हिना खान ने खुले कर्ल वाले हेयर स्टाइल के साथ लुक को पूरा किया। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हिना खान ने कैप्शन लिखा, कभी ना कभी। हिना खान की फोटोज को देखकर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं और उनकी खूबसूरती की साथ ही उनके स्टाइल की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

रंजिश में व्यापारी को कार से कुचलने की कोशिश, रिपोर्ट दर्ज

लखनऊ। मलिहाबाद कस्बे में दो दिन पूर्व दो दुकानदारों के बीच हुई कहासुनी में एक पक्ष ने दूसरे व्यापारी को कार से कुचलने का प्रयास किया। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मलिहाबाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया है। प्रभारी निरीक्षक सुरेश सिंह के मुताबिक, क्षेत्र के एखलाक की मलिहाबाद चौराहा माल रोड पर दुकान है। इसी मार्ग पर बस्ती धनवंत राय निवासी मो. शुऐब की दुकान है। बताया कि दो दिन पूर्व दोनों दुकानदारों के बीच कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद से शुऐब एखलाक से रंजिश रखने लगा। मंगलवार दोपहर करीब १२ बजे शुऐब ने एखलाक को कार से कुचलने का प्रयास किया। पीड़ित किसी तरह जान बचाकर भाग निकला। पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। जिसका वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल होने लगा। इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई। एखलाक की लिखित शिकायत पर मो. शुऐब के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि देर शाम आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है।

गुलमर्ग में अपना ४२वाँ जन्मदिन मना रही हैं एक्ट्रेस निम्रत कौर

मुंबई। एक्ट्रेस निम्रत कौर कश्मीर के गुलमर्ग में बुधवार को अपना ४२वां जन्मदिन मना रही हैं। उन्होंने स्कीइंग करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी कई फोटोज और वीडियो शेयर की। पिछली बार 'सजनी शिंदे का वायरल वीडियो' में दिखाई देने वाली एक्ट्रेस इन दिनों 'भ ारती के स्वर्ग' में छुट्टियों का आनंद

ले रही हैं। निम्रत कौर एक्ट्रेस ने आज इंस्टाग्राम पर अपने पहले स्कीइंग अनुभव की वीडियो और तस्वीरें शेयर की। वीडियो में निम्रत को सफेद स्वेटर, काली टाइट्स और लंबी बेज जैकेट में देखा जा सकता है। वह आइस स्केट्स पहनकर विक्ट्री साइन दिखाते हुए खुशी से पोज दे रही हैं। स्कीइंग करते समय एक्ट्रेस पहले थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं। लेकिन बाद में वह खुशी से चिल्लाई "वाह. . मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अन्य वीडियो में निम्रत को खुली जीप में बैठे हुए गुलमर्ग के बर्फ से ढँके पहाड़ों का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। उनकी अगली फिल्म 'सेक्शन ८४' पाइपलाइन में है। वह पिछली बार एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज 'स्कूल ऑफ लाइज' में नजर आई थीं।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
lt; ckt ibl
lhrkiqj
eks-9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
lqjs'k ukjk;.k feJ
क्षेत्रीय सम्पादक
lkjHk dqekj] fcgkj
eks-09386075289
मो० अरशद
C;jks phQ
eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित। आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar @yahoo.in adbhut_samachar @rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक